भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 326
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023 (15 अग्रहायण, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

326 **डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे :**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चरणबद्ध तरीके से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की देश में लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का खाका तैयार करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन-2018 के सांख्यिकीय प्रोफाइल के अनुसार 30-09-2023 तक देश में सहकारी समितियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, विभिन्न अधिनियमों के तहत पंजीकृत और विभिन्न क्षेत्रों के तहत काम करने वाली सहकारी समितियों के बारे में जानकारी तक वास्तविक समय में एकल बिंदु पहुंच प्रदान करने और सभी सहकारी समितियों के संसाधनों की योजना बनाने, निगरानी करने और उन्हें चैनलाइज़ करने के लिए, जिससे सहकारी को बढ़ावा मिले। देश में आंदोलन, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र की विविध प्रकृति और आकार को ध्यान में रखते हुए, तीन चरणबद्ध तरीके से डेटा संग्रह करके डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया गया।

i. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-I: प्रथम चरण के तहत, तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग फरवरी, 2023 में पूरी की गई। इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रथम चरण में मैप की गई सोसायटी की संख्या क्रमशः 1,03,448 (PACS), 25,528 (डेयरी) और 1,41,320 (मत्स्य पालन) रही ।

ii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण- II: द्वितीय चरण के तहत, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों की उनके सामान्य निकाय के सदस्यों के साथ मैपिंग पूरी की गई। इसके अलावा, राज्य संघों, जिला संघों और प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ राष्ट्रीय संघों को भी जोड़ा गया। राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी), चीनी सहकारी मिलों, राज्य संघों, जिला संघों और बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित डेटा सीधे सहकारी समिति से या उनके राष्ट्रीय/राज्य संघों के माध्यम से एकत्र किए गए ।

iii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-III: तृतीय चरण के तहत, सहकारिता मंत्रालय ने मई, 2023 में राज्य के राज्य सहकारित पंजियक (आरसीएस) कार्यालय के माध्यम से अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने वाली शेष 5 लाख से अधिक सहकारी समितियों तक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू की। केरल और मणिपुर को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के तहत (97%) डेटा प्रविष्टियाँ पूरी कर ली हैं।

(ग): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा अपने भारतीय सहकारी आंदोलन- एक सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल-2018 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, राज्य-वार सहकारी समितियों के डेटा का विवरण अनुबंध- "ए" में रखा गया है।

*****

अनुबंध -ए

एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल-2018 के अनुसार सहकारी समितियों की कुल संख्या	
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	**भारत में कुल सहकारी समितियाँ**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2104
आंध्र प्रदेश	73218
अरुणाचल प्रदेश	783
असम	10246
बिहार	39169
चंडीगढ़	243
छत्तीसगढ	11364
दादरा और नगर हवेली	284
दमन और दीव	106
दिल्ली	6360
गोवा	3822
गुजरात	77550
हरयाणा	24572
हिमाचल प्रदेश	5394
जम्मू और कश्मीर	2020
झारखंड	13855
कर्नाटक	40938
केरल	19263
लक्षद्वीप	81
मध्य प्रदेश	47415
महाराष्ट्र	205886
मणिपुर	9237
मेघालय	1555
मिजोरम	1437
नगालैंड	9059
ओडिशा	17330
पुदुचेरी	532
पंजाब	17437
राजस्थान	28459
सिक्किम	5464
तमिलनाडु	24482
तेलंगाना	65156
त्रिपुरा	2067
उतार प्रदेश	48188
उत्तराखंड	5623
पश्चिम बंगाल	33656
कुल	**854355**